आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड राज्य वर्तमान व्यवस्था बनाये रखने के पक्ष मे थे। इस व्यवस्था क अन्तर्गत तम्बाकू, चीनी तथा सूती-वस्त्रो पर विक्रय-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाया गया था और वे इसे अन्य वस्तुओ पर भी लागू करने के पक्ष मे थे। वर्तमान व्यवस्था को अन्य वस्तुओ पर लागू करने के सम्बन्ध मे आयोग ने यह कहा है

> "राज्यो के आम विरोध को देखते हुए, इस व्यवस्था को निकट भविष्य मे अन्य मदो अथवा पदार्थों पर लागू करने की स्पष्टत: कोई गुजाइश नही है।"

दिल्ली प्रशासन की कार्यकारी परिषद् ने भी 4 जुलाई, 1970 को इस आशय का एक सकल्प पारित किया था कि जिन अन्य मदो पर फिलहाल विक्रय-कर लगाया जाता है उन्हे भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। चूकि विक्रय-कर मुख्यत राज्यो की विधायी क्षमता के अन्तर्गत आता है, इसलिये आयोग द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार, राष्ट्रीय विकास परिषद् की मुख्य-मत्रियो की समिति मे, इस मामले पर चर्चा की गई थी। समिति ने यह स्वीकार किया कि चीनी, तम्बाकू तथा सूती वस्त्रों पर राज्य विक्रय-कर के स्थान पर, अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाया जाता रहना चाहिये और ऐसी व्यवस्था की जाय जिसमे अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क से होने वाली आय को बढ़ाया जा सके। जहा तक इस योजना को अन्य वस्तुओ पर लागू करने का सम्बन्ध है, सरकार ने आयोग की सिफारिश स्वीकार कर ली है।

Increase in Emoluments of Bank Employees

1376. **SHRI T. S. LAKSHMANAN**: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the increase in emoluments given to the Bank employees during the last two years and the cost of such increase to the Banking industry; and

(b) whether similar increase has been given to any other category of employees in Central Government or public sector undertakings?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN). (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Life Insurance Policy Holders

1377. SHRI T. S LAKSHMANAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of Life Insurance policy holders in urban areas and rural areas,

(b) the increase in the number of Life Insurance Corporation policies in urban and rural arears over the last three years, and

(c) the reasons for the slackness is increase in the number of Life Insurance Corporation's policies in rural areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH). (a) and (b) The final figures of new business secured by the L. I. C. separately in the urban and the rural areas during the year 1970-71 are not yet available. The total number of policies issued during that year was, however, 16,18,690 assuring a sum of more than Rs. 1303 crores.

The business secured by the L. I. C. during the preceding three years was as under:

(in crores of rupees)

	No of policies		*Sum assured*	
	Urban	Rural	Urban	Rural
1967-68	9,13,709	5,09,607	599.82	235.46
1968-69	9,72,671	4,77,341	685.32	235.12
1969-70	9,35,063	4,61,468	773.92	251.76

(c) The number of policies has been going down in the last three years even though there has been no fall in the sums assured. The reasons for the failure of the L. I. C. to register an increase in rural business, in its judgment, are:—

(i) Variations in income due to seasonal and other factors;